(c) whether Government propose to go on with the demarcation work on their own?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) The East Pakistan Survey officials unilaterally stopped demarcation work on the West Bengal-East Pakistan border.

(b) According to our information, the pillars were removed by Pakistani nationals.

(c) Since demarcation of the international boundary with Pakistan is a joint operation, it would not be possible to proceed with the work without the cooperation of the Pakistani authorities.

Decrease in Plan Provision for Himachal Pradesh

*1032. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Plan Provision for Himachal Pradesh during the last two years has been progressively reduced;

(b) whether in view of the fact that the area of Himachal Pradesh as a result of reorganisation of Punjab has doubled, the allocation is patently inadequate for the development of Himachal Pradesh; and

(c) the justifications of this inadequate allocation and whether Government will consider reassessment of the needs of the area?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) The outlay approved by the Planning Commission for the year 1967-68 was 15.72 crores which was a substantial increase over the previous year's outlay of 9.0 crores. This was intended mainly to provide for the development of the Hill Areas transferred to Himachal from old Punjab.

(c) Does not arise.

कनाडा के पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य

*1033 **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कनाडा के पुनर्वास मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उनकी सरकार कीनिया के कुछ भारतीयों को कनाडा जाने की अनुमति देने के लिए तैयार है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कनाडा सरकार अथवा किसी अन्य देश के साथ कोई बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). राष्ट्र मंडल आप्रवास अधिनियम के कारण खड़ी होने वाली समस्याओं के बारे में भारत सरकार के विचार राष्ट्रमंडल की सभी सरकारों को बता दिए गए हैं । जिन व्यक्तियों पर इसका असर होगा वे चूंकि ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं, इस कारण यूनाइटेड किंगडम की सरकार ही उनके प्रति जिम्मेदार है। बहरहाल, भारत सरकार का ध्यान कनाडा के पुनर्वास मंत्री के इस बयान की ओर आकृष्ट हुआ है कि कीनिया के कुछ एशियाइयों को, जो शिक्षित और कुशल हैं, कनाडा में आने दिया जा सकता है बशर्ते कि वे कनाडा की आप्रवास संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हों ।